भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 637

(दिनांक 03.12.2025 को उत्तर के लिए)

पीएम पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल

637. श्री गौरव गोगोई :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल (पीएमएचआरसी) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस काउंसिल को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया है और यदि हाँ, तो अधिसूचना की तिथि, संरचना और इसका निर्धारित अधिदेश क्या है और यदि नहीं, तो इसमें देरी के कारण और इसके गठन की प्रस्तावित समय-सीमा क्या है; और

(ग) क्या 2020 से पीएमएचआरसी से संबंधित कोई बैठक या प्रारंभिक परामर्श आयोजित किए गए हैं और यदि हाँ, तो इसकी तिथियों और प्रमुख परिणामों सहित ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) : मिशन कर्मयोगी, राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) को सभी सरकारी कर्मचारियों के भूमिका आधारित क्षमता विकास के लिए सितम्बर, 2020 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस मिशन के तहत, क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) और विशेष प्रयोजन साधन - कर्मयोगी भारत को क्रमश: क्षमता निर्माण संबंधी नवाचारों के लिए थिंक टैंक के रूप में और आईगॉट प्लेटफॉर्म के कस्टोडियन के रूप में गठित किया गया है। सभी हितधारकों के बीच भूमिका की स्पष्टता के लिए मिशन कर्मयोगी संबंधी दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। वर्तमान में, आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 1.41 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता शामिल हो चुके हैं और इस प्लेटफॉर्म पर विषय-क्षेत्र (डोमेन), कार्यात्मक एवं व्यवहारात्मक दक्षताओं संबंधी 3700 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। ये पाठ्यक्रम, हिंदी में 735 और अन्य भारतीय भाषाओं में 544 सहित, भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं, जिससे क्षेत्रीय क्षमता निर्माण संबंधी अपेक्षाओं के साथ संरेखण और वृहत्तर पहुंच संभव होती है। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एकक (सीएससीयू) द्वारा मिशन कर्मयोगी के कार्यान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन किया जा रहा है।

*****